

Regarding sand mining in Mahanadi basin

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है। यह नदी न केवल इन राज्यों के लाखों लोगों के जीवन का आधार है, बल्कि यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। महानदी पर निर्भर कृषि क्षेत्र और आबादी का आकार बहुत बड़ा है। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ महानदी का जलग्रहण क्षेत्र, लाखों किसानों की कृषि आय का मुख्य स्रोत है। इस नदी के पानी पर लगभग 70 लाख लोगों का जीवन-यापन निर्भर करता है।

जिसमें प्रमुख रूप से जल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन, और जल परिवहन शामिल हैं। हाल ही में, इस नदी के किनारे रेत के अवैध उत्खनन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे नदी के पारिस्थितिक तंत्र में गंभीर बदलाव आ रहे हैं। इस अवैध खनन के कारण जल स्तर में गिरावट, नदी के प्रवाह में रुकावट और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जो कि स्थानीय समुदायों के लिए संकट का कारण बन रहा है। इससे प्रभावित कृषि भूमि, जल आपूर्ति, और मछली पालन जैसी गतिविधियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या सरकार इस अवैध रेत खनन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रही है, ताकि महानदी के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूँ कि इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए।